

[2023] 7 एस. सी. आर 1082

आधिकारिक समकक्ष

वी.

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस।

(2010 की सिविल अपील सं. 8015)

04 मई, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 आर। 338 - मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 - s.185-परिसमापन के बाद का दायित्व, यदि आधिकारिक परिसमापक (ओ. एल.) परिसमापन के लिए बाध्य था-क्या परिसमापन में कंपनी के संपत्ति कर और जल कर के बकाया के लिए प्रतिवादी संख्या 1-निगम द्वारा किए गए दावे, परिसमापन के बाद की अवधि (परिसमापन के आदेश की तारीख से और नीलामी खरीदार को परिसंपत्तियों की बिक्री की पुष्टि की तारीख तक) से संबंधित, यदि अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकार्य हो-ओ. एल.-आयोजित: हां-वर्तमान मामले में, बिक्री सूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार,

बिक्री "जैसा भी है, जो कुछ भी है" के आधार पर थी-एक और अस्वीकृति यह भी कहा गया था कि अपीलकर्ता-ओ. एल. बेची गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, मात्रा या विनिर्देश के रूप में कोई गारंटी प्रदान नहीं कर रहा था-इस तरह की शर्तों और अस्वीकृतियों ने निश्चित रूप से खरीदारों को इस बात से परिचित कराने के लिए नोटिस दिया था कि संपत्ति क्या है (प्रकृति और विस्तार); वह कहाँ है (स्थान)।

विशेषताएँ); और जो कुछ भी है (इसकी मात्रा और शर्त)-बोलीदाताओं/खरीदारों को आगे खुद को संतुष्ट करने के लिए चेतावनी दी गई थी

परिसंपत्तियों के भौतिक निरीक्षण के बाद प्रकृति, विस्तार, स्थान आदि के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और यह भी सूचित किया गया कि उन्हें दोषों, यदि कोई हों, के बारे में पूरी जानकारी के साथ पेशकश करने के लिए माना जाएगा-हालाँकि, उन नियमों और शर्तों में महत्वपूर्ण चूक बोली लगाने वाले/खरीदार के लिए यह अनिवार्य बनाना था कि वह स्वयं को निहित परिसंपत्तियों से जुड़े बोझ, ग्रहणाधिकार और दावों के बारे में जागरूक करे। 185 , विचाराधीन संपत्ति पर एम. पी. अधिनियम, 1956, बोलीदाता/खरीदार इस धारणा पर आगे बढ़ने का हकदार था कि भले ही एम. पी. अधिनियम, 1956 के तहत ऐसे करों का कोई बकाया हो, लेकिन वह उससे वसूल करने योग्य नहीं होगा-कंपनी

न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दावा किए गए संपत्ति कर और जल कर के कारण देयता को कंपनी द्वारा खारिज कर दिया गया था।

1082 आधिकारिक समकक्ष v. उज्जैन नगर पालिका

& ओआरएस।

अपीलार्थी-ओ. एल. परिसमापन के बाद का दायित्व था, जिसे ओ. एल. आर. के संचालन को देखते हुए बिक्री सूचना में चूक को देखते हुए निर्वहन करने के लिए बाध्य था। 338, 1959 नियम-किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, नीलामी खरीदार बिना किसी सूचना के

परिसमापन के बाद की अवधि के दौरान कर के बकाया के लिए किसी भी शुल्क को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है-संपत्ति कर का बकाया

बिक्री की पुष्टि की तारीख तक जल कर परिसंपत्तियों के "संरक्षण, प्राप्ति या अधिग्रहण" के लिए खर्च के रूप में योग्य होगा।

कंपनी और इस प्रकार, अपीलकर्ता ओ. एल. द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करता है

कंपनी अधिनियम, 1956-एस. 529ए, 530।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य।

(1994) 1 एस. सी. सी. 575 [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1; हरियाणा वित्तीय निगम बनाम। राजेश गुप्ता (2010) 1 एससीसी

655 [2009] 16 एससीआर 456-प्रतिष्ठित।

यूटी चंडीगढ़ प्रशासन और ए. एन. आर. वी. अमरजीत सिंह और ओआरएस। (2009) 4 एससीसी 660: [2009] 4 एस. सी. आर. 541; पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण बनाम।

रघु नाथ गुप्ता (2012) 8 एससीसी 197: [2012] 8 एससीआर

118 - अप्रयोज्य रखा गया।

अहमदाबाद नगर निगम बनाम। हाजी अब्दुल गफूर

हाजी हुसैनभाई (1971) 1 एस. सी. सी. 757; ए. आई. चम्पदानी लिमिटेड बनाम। आधिकारिक परिसमापक और एएनआर। (2009) 4 एससीसी 486:

[2009] 2 एस. सी. आर. 705 पर भरोसा किया।

नगरपालिका बोर्ड, कानपुर बनाम। रूप चंद जैन और

एन. आर. ए. आई. आर. 1940 सभी 456-संदर्भित।
दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। (2016) 13 एससीसी 561:

[2016] 3 एस. सी. आर. 1126-संदर्भित।

तोशोकू फाइनेंस यूके पीएलसी: [2002] 1 डब्ल्यूएलआर 671; इन री तोशोकू फाइनेंस यूके पीएलसी-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1993] 3 पूरक। एससीआर 1

प्रतिष्ठित

पैरा 8.3

[2009] 16 एससीआर 456

प्रतिष्ठित

पैरा 9

अप्रयोज्य रखा गया

[2009] 4 एससीआर 541

पैरा 9 [2023] एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 8 एससीआर 118

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 9

(1971) 1 एस. सी. सी. 757

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[2009] 2 एससीआर 705

उस पर भरोसा करें

पैरा 12.3

[2016] 3 एससीआर 1126

पैरा 12.5

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 8015

2010 से।

उच्च न्यायालय के 05.02.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 के ए. सी. ओ. सं. 49 और 2008 के ए. पी. ओ. टी. सं. 248 में कलकत्ता से।

2010 की सिविल अपील सं. 8016।
श्रीमती रूपाली सामंत घोष, संजय कुमार घोष, अधिवक्ता। के लिए
अपीलार्थी।

सुश्री क्रिस्टी जैन, पुनीत जैन, हर्षित खांडुजा, योगित कामत,

एम. अरोड़ा, सुश्री प्रतिभा जैन, सुनील रॉय, टी. श्रीनिवास मूर्ति, पी. एन. गुप्ता, श्रीमती भारती गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

1. इन अपीलों के माध्यम से, अपीलार्थी, आधिकारिक परिसमापक होने के नाते 1

आई. आई. एस. सी. ओ. की उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड 2 ने 2008 के ए. पी. ओ. टी. संख्या 248 और 2008 के ए. पी. ओ. टी. संख्या 235 में दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश पर सवाल उठाया है, जिसके तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2006 के सी. ए. संख्या 159 और 2006 के सी. ए. संख्या 160 में दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया है, जैसा कि उच्च न्यायालय के विद्वान कंपनी न्यायाधीश 3 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा कंपनी के आवेदनों को अनुमति देने में पारित किया गया था, जिसमें परिसमापन में कंपनी के संबंध में अपीलकर्ता से संपत्ति कर और जल कर का दावा किया गया था।

नीलामी खरीदार को परिसंपत्तियों की बिक्री की पुष्टि की तारीख, जिसका प्रतिनिधित्व अब प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाता है।

1 'ओएल', संक्षेप में। 2 इसके बाद इसे 'परिसमापन में कंपनी' भी कहा जाता है। 3 इसके बाद इसे 'कंपनी न्यायालय' भी कहा जाता है।

4 इसके बाद इसे 'निगम' भी कहा जाता है।

आधिकारिक समकक्ष v. उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1956 के प्रावधान। बी. आई. एफ. आर. ने इसे समाप्त करने की सिफारिश की और तदनुसार, कंपनी न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के अपने आदेश में इसे समाप्त करने का आदेश दिया गया। इसमें अपीलार्थी को आधिकारिक परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था और

परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का निर्देश दिया।

3. 04.04.2003 पर कंपनी अदालत द्वारा पारित एक आदेश के बाद, परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों को "जैसा है वैसा" पर बिक्री के लिए रखा गया था। दिनांकित 09.05.2003 की बिक्री सूचना के माध्यम से जो कुछ भी आधार है वह कहाँ है? उक्त सूचना में इच्छुक खरीदारों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों के निरीक्षण के लिए प्रावधान किया गया था और शर्तों की उपलब्धता का उल्लेख किया गया था

और अपीलार्थी के कार्यालय में कंपनी की परिसंपत्तियों के बारे में विवरण के साथ बिक्री की शर्तें। यह बिक्री सूचना इस प्रकार है:

" बिक्री सूचना

अदालत, कलकत्ता ने कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए वास्तविक धन के रूप में प्रस्तावित राशि के 20 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए। जैसे कि देवास रोड, उज्जैन एम. पी. में स्थित भूमि संरचना, भवन, मशीनरी आदि और नाना-खेड़ा, इंदौर रोड, उज्जैन, एम. पी. में लीज होल्ड लैंड बिल्डिंग क्वार्टर। शेष राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाना है और खरीद मूल्य के पूर्ण भुगतान के बाद ही कब्जा नहीं किया जाता है। मुहरबंद प्रस्ताव आधिकारिक परिसमापक द्वारा दिनांक 26 जून 2003 को शाम 5 बजे प्राप्त किए जाएंगे और उन्हें 27 जून 2003 को दोपहर 2 बजे माननीय न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले खोला जाएगा।

विचार के लिए कलकत्ता में उच्च न्यायालय में कंपनी के मामले इस तरह के सीलबंद प्रस्ताव। किसी को भी पक्ष में खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।

नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति।

कंपनी की परिसंपत्तियों का निरीक्षण। होगा।

26 मई 2003 को इच्छुक खरीदारों को अनुमति दी गई और

संक्षेप में, 'बीआईएफआर'।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27 मई 2003 दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच। [परिसमापन में] कंपनी की परिसंपत्तियों के विवरण के साथ बिक्री के नियम और शर्तें 22 मई 2003 को और उससे कार्यालय के समय के दौरान Rs.50/की कीमत पर अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति के कार्यालय में उपलब्ध होंगी। प्रति सूची और निरीक्षण अवधि के दौरान स्थल पर भी।

मई, 2003 के इस 9वें दिन की तारीख।

3.1 . उपर्युक्त बिक्री सूचना में कुछ नियम और शर्तें संलग्न की गई थीं, जो इस बात को पुष्ट करती थीं कि बिक्री "जैसा कुछ भी है वैसा ही" आधार पर होगी और यह कहते हुए कि अपीलकर्ता ओ. एल. बेची गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, मात्रा या विनिर्देश के बारे में कोई गारंटी प्रदान नहीं करेगा; निविदाकारों को कंपनी की परिसंपत्तियों के भौतिक निरीक्षण के बाद इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना था; और

खरीदारों को बेची गई परिसंपत्तियों के विवरण, गुणवत्ता या मात्रा में दोष, यदि कोई हो, के बारे में पूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत करना माना जाएगा। वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक शर्तों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

निम्नलिखित है:

" बिक्री की शर्तें और शर्तें

1. बिक्री मूल्यांकनकर्ता द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार 'जहां कुछ भी है' के आधार पर होगी, बशर्ते कि माननीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाए, आधिकारिक परिसमापक बेची गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, मात्रा या विनिर्देशन के बारे में कोई गारंटी और/या वारंटी प्रदान नहीं करेगा। निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं को कंपनी की परिसंपत्तियों के भौतिक निरीक्षण के बाद इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना होगा और खरीदारों को बेची गई परिसंपत्तियों के विवरण, गुणवत्ता या मात्रा में दोष, यदि कोई हो, के बारे में पूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत करना माना जाएगा। अधिकारी ने

परिसमापक, बिक्री समाप्त होने के बाद इस संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा। निविदा आमंत्रित करने के नोटिस में कोई गलती होगी

बिक्री को खराब न करें।

3.2 . उपरोक्त बिक्री सूचना के अनुसार, संपत्ति को नागेंद्र जैन को रुपये की राशि में बेचा गया था। 20.50 करोड़; और बिक्री

कंपनी अदालत के दिनांक 04.07.2003 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई थी। तत्पश्चात, परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों के खरीदार के रूप में उक्त नागेंद्र जैन के स्थान और स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 को नामित किया गया था।

आधिकारिक समक्ष v. उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

4. परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, अपीलार्थी ओ. एल. ने विज्ञापनों के माध्यम से परिसमापन में कंपनी के लेनदारों से दावे आमंत्रित किए।

5. अपने दावे की आंशिक अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 निगम ने कंपनी के समक्ष दो कंपनी आवेदनों को प्राथमिकता दी। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 164 के तहत न्यायाधीश के समन द्वारा कलकत्ता में न्यायालय, विशेष रूप से परिसमापन के बाद के दावों की स्वीकार्यता के संबंध में।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इस प्रकार पसंद किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए, कंपनी न्यायालय ने निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया:

" इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह है कि क्या दावे, जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक परिसमापक के खिलाफ उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी अवधि के लिए परिसमापन, के क्रम के बाद

समाप्त करना, पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है। "

6.1 . कंपनी न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 निगम आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया था कि ओ. एल. दोनों के लिए उत्तरदायी है। परिसमापन से पहले और परिसमापन के बाद की दरें और कर; कि धारा के अनुसार

' इसके बाद '1959 के नियम' के रूप में भी संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

185 मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति एक सुरक्षित लेनदार की थी। और यह कि किसी भी मामले में, ओ. एल. को दावे की अस्वीकृति के लिए कारण देने की आवश्यकता थी जो उसने नहीं किया था। 1959 के नियमों के नियम 163 का भी संदर्भ दिया गया था।

6.2 . इसी तरह, प्रत्यर्थी संख्या 3 नीलामी खरीदार की ओर से 1956 के एम. पी. अधिनियम की उक्त धारा 185 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया था कि वह उस तारीख से पहले ऐसे करों के लिए उत्तरदायी नहीं था जिस दिन उसने संपत्ति पर कब्जा किया था। और यह कि ओ. एल. खरीदार के पक्ष में परिवहन विलेख के निष्पादन तक सभी करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

6.3 . दूसरी ओर, अपीलार्थी ओ. एल. की ओर से यह तर्क दिया गया कि वह केवल उन करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो आज तक उपार्जित हुए हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 3 की धारा 529ए को देखते हुए, श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदारों के बकाया का भुगतान समान रूप से किया जाना था, और अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता दी जानी थी; और वह नियम 154

1959 के नियमों में सुसंगत तिथि पर ऋण के प्रमाण का शपथ पत्र दाखिल करने का प्रावधान किया गया था और अपीलार्थी ने सुसंगत तिथि पर देय करों की अनुमति दी थी जो साबित हो चुके थे।

7. आई. डी. 1 दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश में, कंपनी न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 निगम द्वारा इस प्रकार दायर आवेदनों को स्वीकार करते हुए कहा कि अपीलार्थी ओ. एल. का दायित्व केवल समापन के आदेश की तारीख तक दावों और ऋणों तक ही सीमित नहीं था।

7.1 . कंपनी न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलार्थी ओ. एल. द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 530 और कंपनी अधिनियम के नियम 154 पर निर्भरता रखी गई है।

1959 के नियमों को स्पष्ट रूप से गलत समझा गया था, जबकि यह देखते हुए कि उनमें से किसी में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो केवल समापन के आदेश की तारीख तक दावे को प्रतिबंधित करता हो। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 530 किसी कंपनी को राजस्व और करों के प्रति उसके दायित्व के परिसमापन में दोषमुक्त नहीं करेगी और परिसमापन के बाद की अवधि में ऐसी देनदारियों को परिसमापन की लागत का एक हिस्सा माना जाएगा और अन्य सभी देनदारियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक नीलामी खरीदार का संबंध है, कंपनी अदालत ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि खरीदार खरीद की

तारीख से ही संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कंपनी न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की और अभिनिर्धारित किया:

1 इसके बाद इसे '1956 का एम. पी. अधिनियम' भी कहा जाता है। 8 इसके बाद 'कंपनी अधिनियम 3' के रूप में संदर्भित किया गया है।

फिसियल इन्क्रेडिटर v. उज्जैन नगर पालिका निगम

& ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" कंपनी बंद हो सकती है और इसका व्यवसाय बंद हो सकता है।

फिर भी, आधिकारिक परिसमापक परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए बाध्य होगा परिसमापन में कंपनी की, जब तक कि परिसंपत्तियाँ

बेचा जाता है। परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए, आधिकारिक परिसमापक

आवश्यक समझते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ किराया, बिजली का दावा कर सकते हैं। समाप्त होने की तारीख के बाद उपार्जित शुल्क एकमुश्त होना चाहिए

खारिज केवल इस आधार पर किया गया कि दावे परिसमापन के बाद के थे

दावा भले ही परिसमापन में कंपनी के पास पर्याप्त हो

दावों को पूरा करने के लिए धन?

श्री घोष के तर्क के अनुसार, एक बिजली आपूर्तिकर्ता के पास हो सकता है

बकाया राशि का भुगतान न करने पर आपूर्ति बंद करने का विकल्प और

उपभोक्ता की प्रतिभूति जमा को विनियोजित करना। का अधिकार हालांकि, डिस्कनेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा

आपूर्तिकर्ता के दावे की रखरखाव क्षमता। यह विवाद में नहीं है कि आधिकारिक परिसमापक बना रहा है

परिसमापन के बाद बिजली शुल्क का भुगतान। मजबूरी है कि

हालांकि, भुगतान करने से कानूनी रूप से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है।

दावे की स्थिति।

परिसमापन देय है, इसलिए किराया भी देय है। किसी कंपनी का दायित्व किराया और/या व्यवसाय शुल्क और/या दरों और करों का भुगतान करता है

बंद करने के क्रम के साथ स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होता है

कंपनी ने।

10 तारीख के बीच की अवधि के लिए दरों और करों के संबंध में जुलाई, 1997 वह तिथि थी
जिस पर कंपनी को निर्देश दिया गया था

4 जुलाई, 2003 को बिक्री की तारीख होगी।

आधिकारिक परिसमापक ने अपने ऋण के प्रमाण को अस्वीकार कर दिया है। कंपनी
अधिनियम और [2023] 7 एस. सी. आर. के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी (न्यायालय) नियम जिसके तहत बनाए गए हैं और विशेष रूप से नियमों की धारा 528, 529ए और 530 और नियम 154।

आधिकारिक परिसमापक की ओर से यह तर्क कि ऋण और दावे और विशेष रूप से नगरपालिका कर के कारण दावे केवल कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 को ध्यान में रखते हुए कंपनी के समापन की तारीख तक देय हैं, कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 154 के साथ पढ़ा जाता है, स्पष्ट रूप से गलत धारणा है। कंपनी अधिनियम या कंपनी (न्यायालय) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो केवल समापन आदेश की तारीख तक दावों और ऋणों को प्रतिबंधित करता हो।

परिसमापक ने परिसंपत्तियों और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया कंपनी का अनुमान अनिवार्य रूप से अधिकारी द्वारा लगाया जाना चाहिए

उपलब्ध अभिलेखों और दावेदार और/या लेनदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर परिसमापक। परिसमापन के बाद के ऋणों और दावों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 530 किसी कंपनी को परिसमापन में दोषमुक्त नहीं करती है।

उपकर और दरें जो संबंधित तिथि से 12 महीने के भीतर देय और देय हो गईं, जो अन्य पूर्व-परिसमापन ऋणों की प्राथमिकता में समापन आदेश की तारीख है। परिसमापन के बाद की देनदारियों को कंपनी को बंद करने की लागत के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। परिसमापन और ऐसी देनदारियों को कंपनी की अन्य सभी देनदारियों पर प्राथमिकता मिलती है।

यह सच है कि आधिकारिक परिसमापक ने कोई व्यवसाय नहीं किया था कंपनी की ओर से। हालांकि, आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी के लाभकारी समापन के लिए अपना अधिकार बरकरार रखा।

आधिकारिक समक्ष v. उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा न्यायमित्र के रूप में नियुक्त श्री मुखर्जी और आवेदक की ओर से उपस्थित श्री बनर्जी द्वारा उचित तर्क दिया गया है, समापन में किए गए खर्च देय हैं, जो सिद्ध करने योग्य नहीं हैं। कुछ लेनदारों की प्राथमिकता का सिद्धांत उस समय कंपनी के दायित्व पर लागू होता है जब कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया था। कंपनी के समापन में कंपनी की ओर से की गई लागत और खर्च का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए था।

7.2 . कंपनी न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अपीलार्थी ओ. एल. ने दावों को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह परिसमापन के बाद के खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लेकिन उसने न तो वार्षिक मूल्य के निर्धारण पर आपत्ति जताई थी और न ही 1956 के एम. पी. अधिनियम की धारा 184 के तहत कोई अपील दायर की थी। न्यायालय ने कहा कि जब तक कोई आपत्ति या अपील दायर नहीं की जाती और मांग कम नहीं की जाती, ओ. एल. निगम के दावे के अनुसार, परिसमापन के बाद की अवधि के लिए भी कर देयता का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगा। इसलिए, अदालत ने अस्वीकृति नोटिस को रद्द कर दिया

अपीलार्थी द्वारा लेकिन उसे मांगों के खिलाफ अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई, यदि इस प्रकार चुना जाता है, तो तीस दिनों के भीतर और यह भी प्रावधान किया गया है कि अपीलार्थी, एम. पी. अधिनियम 1956 की धारा 184 के तहत अपील में आदेश प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर, आवेदक (प्रतिवादी संख्या 1) के दावों पर विचार करेगा और उनका निपटान करेगा, जैसा कि अपील में और कानून के अनुसार निर्धारित किया गया है। 8. अपीलार्थी ने डिवीजन के समक्ष अपील के माध्यम से कंपनी न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और दिनांक 1 के आदेश को चुनौती दी।

लेकिन, उच्च न्यायालय की पीठ ने विवादित निर्णय और दिनांक 05.02.2009 के आदेश द्वारा अपीलों को खारिज कर दिया। 8.1 . अपीलार्थी ओ. एल. ने डिवीजन बेंच के समक्ष तर्क दिया

कि उसने कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं किया था और इसके परिणामस्वरूप,

परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के उपयोग से किसी भी तरह से लाभ अर्जित नहीं किया; कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में संपत्ति और पानी पर परिसमापन के बाद के करों के भुगतान की परिकल्पना नहीं की गई थी और परिसंपत्तियां केवल परिसमापन आदेश के बाद बिक्री तक वैध थीं; और यह कि बिक्री "जैसा कुछ भी है वैसा ही" आधार पर थी, जिसका अर्थ यह होगा कि परिसंपत्तियां बेचे जाने पर बोझ से मुक्त नहीं थीं और इस तरह, करों का दायित्व खरीदार को स्थानांतरित कर दिया गया था।

8.2 . प्रत्यर्थी संख्या 1 निगम ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता बिक्री आय में से निगम को करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और इसके अलावा, कंपनी न्यायालय के समक्ष की गई प्रस्तुतियों को दोहराया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसी तरह, नीलामी खरीदार, प्रत्यर्थी संख्या 3, ने प्रस्तुत किया कि वह न तो मालिक था और न ही अधिभोगकर्ता जब तक कि बिक्री की पुष्टि नहीं हो गई थी और इसलिए, शुल्क को बिक्री आय में स्थानांतरित किया जाएगा न कि खरीदार को। हालांकि, कंपनी के एक लेनदार, प्रतिवादी संख्या 2 ने तर्क दिया कि बकाया के लिए दावा संपत्ति और जल कर का भुगतान नीलामी खरीदार के खिलाफ किया जाएगा न कि ओ. एल. के खिलाफ।

8.3 . खंड पीठ ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 3-नीलामी

क्रेता-परिसमापन के बाद उपार्जित उक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि बिक्री के नियमों और शर्तों से यह पता नहीं चल सका कि क्रेता को निगम के बकाया के प्रति किसी भी दायित्व के बारे में सूचित किया गया था। डिवीजन बेंच ने कहा कि बिक्री सूचना में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में कि इच्छुक खरीदार को कंपनी की परिसंपत्तियों के परिसमापन के संबंध में सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करना होगा।

अड़चनों में, अपीलार्थी परिसमापन के बाद संपत्ति और जल करों के प्रति दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य था; और यह कि यह नहीं होगा

बिक्री से पहले किसी खरीदार को बोझ के बारे में सूचित किए बिना उस पर दायित्व तय करना उचित है। डिवीजन बेंच ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले को भी अलग किया। आधिकारिक परिसमापक और अन्य। : 79 कंपनी के मामले 262 [= (1994) 1 एस. सी. सी. 575] उस मामले में विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स और बिक्री के विशिष्ट नियमों और शर्तों पर ध्यान देते हुए। वर्तमान मामले में बिक्री के नियमों और शर्तों और उपरोक्त मामले में बिक्री की शर्तों के बीच तुलना करने के बाद, यह देखा गया कि वर्तमान मामले में बिक्री सूचना समान और व्यापक भाषा में नहीं दी गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में, यदि कोई बोझ है, जिसके बारे में खुद को जागरूक करने का कोई अवसर नहीं था, जिसे वह खरीदना चाहता था।

8.4 . जहाँ तक कंपनी अधिनियम की धारा 530 की प्रयोज्यता का संबंध है, डिवीजन बेंच ने कहा कि उक्त प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है

उन करों के भुगतान के साथ जो तारीख के बीच हो सकते हैं

परिसमापन का आदेश और उसकी परिसंपत्तियों की बिक्री की तारीख। इसी तरह, 1959 के नियमों के नियम 154, जिसमें कंपनी को बंद करने के आदेश की तारीख को ऋणों और दावों के मूल्य के आकलन का तरीका प्रदान किया गया था, को कोई आवेदन नहीं माना गया था।

8.5 . उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा और कहा कि

इसके अंतर्गत:

फिसियल इन्क्रेडिटर v. उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" बिक्री सूचना में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि पानी और संपत्ति करों के कारण शुल्क वहन करने का दायित्व खरीदार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि "जैसा भी है, जो भी आधार है" अभिव्यक्ति में इसके दायरे में वैधानिक आरोपों को हटाने का दायित्व शामिल है। अर्जित किया है और बकाया में हैं। बिक्री के नियम और शर्तें यह निर्दिष्ट करती हैं कि आधिकारिक परिसमापक बेची गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, मात्रा या विनिर्देशन के बारे में कोई गारंटी और/या वारंटी प्रदान नहीं करेगा और इच्छुक खरीदार को परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के भौतिक निरीक्षण के बाद इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना आवश्यक है और बेची गई परिसंपत्तियों के विवरण, गुणवत्ता या मात्रा में दोषों के बारे में कोई शिकायत, यदि कोई हो, बिक्री समाप्त होने के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी और निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस में कोई भी गलती बिक्री को दूषित नहीं करेगी। ये, प्रति से, हमारी राय में, एक प्रतिनिधित्व के लिए किए जाने के समान नहीं होंगे

क्रेता का इरादा है कि बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाते समय उसे निगम के बकाया के लिए भी खर्च वहन करना होगा। बेची गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, मात्रा या विनिर्देशन के बारे में गारंटी और/या वारंटी को उससे जुड़ी देनदारी के बराबर नहीं माना जा सकता है। निविदा के नियम और शर्तें केवल गुणवत्ता, मात्रा और विनिर्देशन की सीमा तक आधिकारिक परिसमापक की रक्षा करती हैं और निगम द्वारा दावा किए गए करों को चुकाने के लिए प्रतिरक्षा का दावा करने तक विस्तारित नहीं होती हैं।

आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी अधिनियम की धारा 530 और कंपनी (न्यायालय) नियमों के नियम 154 पर बहुत जोर दिया है। हम वर्तमान विवाद पर निर्णय के लिए उक्त प्रावधानों की भौतिकता का पता लगाने में विफल रहे हैं। धारा 530 में प्रावधान है -

समापन आदेश की तारीख को स्थानीय प्राधिकरण और उसके पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान देय और देय होने पर अन्य सभी बकाया पर प्राथमिकता का हकदार होगा। धारा 530 का उन करों के भुगतान से कोई लेना-देना नहीं है जो बढ़ गए होंगे। परिसमापन की तारीख और खरीदार द्वारा अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री के बीच। नियम 154 भी किसी भी तरह से लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यह कंपनी को बंद करने के आदेश की तारीख को ऋणों और दावों के मूल्य के आकलन का तरीका प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारी राय में, किसी खरीदार को इस तरह के दायित्व के बारे में बिक्री से पहले बताए बिना उस पर दायित्व थोपना पूरी तरह से अनुचित होगा। अंतिम खरीदार द्वारा अपनी बोली लगाने से पहले स्थल पर पूछताछ की गई होगी। खरीदार को वहाँ बाधाओं के बारे में सूचित किया जा सकता था। शेष बिक्री पर विचार जमा करने से पहले भी उन्हें इसके बारे में बताया जा सकता था। निगम द्वारा दायर आवेदनों पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए आधिकारिक परिसमापक को कोई अवसर दिए बिना कंपनी अदालत के समक्ष कार्यवाही का निर्णय लिया गया, जैसा कि स्थगन याचिकाओं से प्रतीत होता है। तथापि, हम स्थगन याचिकाओं में इस आशय का कोई प्रमाण नहीं पाते हैं कि प्रत्यर्थी के बाद नहीं। 3 परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए रुचि व्यक्त की थी, आधिकारिक परिसमापक ने उन्हें इस बात से अवगत कराया था कि ऐसी परिसंपत्तियों की खरीद के साथ निगम द्वारा वसूली योग्य बकाया करों का भुगतान करने का दायित्व भी होगा। इस तरह के कथन के अभाव में, हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि प्रतिवादी नहीं। 3 आधिकारिक परिसमापक के बजाय दायित्व वहन करना चाहिए।

श्री घोष द्वारा उद्धृत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय। आधिकारिक परिसमापक ने उस मामले में कंपनी की परिसंपत्तियों को परिसमापन के नियमों और शर्तों के आधार पर बेच दिया था। त्रिपुटी जूट इंडस्ट्रीज को बिक्री। ऐसे नियमों और शर्तों का खंड (2) इस प्रकार था:

" 2. बिक्री इन्वेंट्री सूची के अनुसार 'जैसा है जहां है' के आधार पर होगी और यह माननीय की पुष्टि के अधीन होगी।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आधिकारिक परिसमापक अचल संपत्तियों के संबंध में और गुणवत्ता, मात्रा या वारंटी के संबंध में कोई गारंटी और/या वारंटी प्रदान नहीं करेगा।

चल परिसंपत्तियों का विनिर्देशन। इरादे वाला

खरीदार को चल और अचल संपत्तियों के संबंध में उनके स्वामित्व, बोझ, क्षेत्र, सीमा, विवरण, गुणवत्ता के संबंध में सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करना चाहिए।

मात्रा और मात्रा आदि और खरीदार को संपत्तियों के विवरण, क्षेत्र आदि और उनके दोष, यदि कोई हों, के बारे में पूरी जानकारी के साथ प्रस्ताव देना माना जाएगा। खरीदार किसी भी खाते पर किसी भी मुआवजे या कीमत में कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा और यह माना जाएगा कि उसने सभी वित्तीय सूचियों के अधीन संपत्ति खरीदी है।

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

श्रम, कर्मचारी आदि को प्रभावित करने वाले मौजूदा कानूनों के तहत आने वाले बोझ, पूर्वाधिकार और दावे। आधिकारिक परिसमापक बिक्री समाप्त होने के बाद इस संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा। नोटिस बुलाने में कोई गलती

निविदा बिक्री को दूषित नहीं करेगी।

यह बिक्री के नियमों और शर्तों के खंड (2) के स्पष्ट प्रावधानों पर विचार करने पर था कि सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़ना शुरू किया

निम्नानुसार धारण करने के लिए:

" जब आधिकारिक परिसमापक न्यायालय के आदेश के तहत परिसमापन में किसी कंपनी की संपत्ति और परिसंपत्तियों को बेचता है।

वह इसके संबंध में कोई गारंटी या वारंटी नहीं दे सकता और न ही देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे परिसमापन में कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।

दिखाएँ। यह इच्छुक खरीदार के लिए है कि वह अचल संपत्ति के स्वामित्व, बोझ आदि के बारे में हर तरह से खुद को संतुष्ट करे जिसे वह खरीदने का प्रस्ताव करता है। वह.

ऐसी शर्तों पर संपत्ति खरीदने के बाद दोष के आधार पर कीमत में कमी का दावा नहीं कर सकते हैं।

संपत्ति के शीर्षक या विवरण में। आधिकारिक परिसमापक द्वारा न्यायालय के आदेशों के तहत किसी कंपनी की संपत्ति को परिसमापन में बेचने का मामला किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अचल संपत्ति बेचने के मामले से बिल्कुल अलग है। इसलिए, कोई योग्यता नहीं है

त्रिपुटी की ओर से किए गए आवेदन में कहा गया है कि कीमत में कमी होनी चाहिए या इसे 1 करोड़ 98 लाख रुपये की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए।

यह समझ में आता है कि एक बार जब किसी इच्छुक खरीदार को अचल संपत्ति के संबंध में सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करने की चेतावनी दी जाती है, जैसा कि उक्त मामले में है, तो यह उसके अपने लाभ के लिए है कि वह अचल संपत्ति के बोझ सहित सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करता है।

जिसे वह खरीदने का प्रस्ताव रखता है। यह भी काफी समझ में आता है कि इस तरह की शर्तों पर संपत्ति खरीदने के बाद कोई भी आपत्ति हो सकती है कि उसे बाधाओं के बारे में पता न हो।

मनोरंजन किया। हालाँकि, यह इस न्यायालय की समझ को पारित करता है कि वर्तमान मामले में बिक्री नोटिस को समान और [2023] 7 एस. सी. आर. में क्यों नहीं जोड़ा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यापक भाषा जिस पर विचार किया जाना था

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। उत्तरदाता नं. के लिए कोई अवसर नहीं है। 3 परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में, यदि कोई बोझ है, जिसके बारे में खुद को जागरूक करने के लिए, जिसे उसने खरीदने का प्रस्ताव किया था, आधिकारिक परिसमापक के लिए यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि उसे पूरी तरह से संतुष्ट होने और प्रासंगिक समय पर कोई आपत्ति नहीं उठाने पर बोली में भाग लेना चाहिए था-केवल वही है जो संपत्ति और अन्य को वहन करने के लिए उत्तरदायी है।

कर।

हमारा विचार है कि निगम द्वारा दावा की गई संपत्ति और जल करों के कारण देयता, आधिकारिक परिसमापक द्वारा खारिज की गई सीमा तक एक परिसमापन के बाद की देयता है जिसे आधिकारिक परिसमापक बिक्री सूचना में एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में निर्वहन करने के लिए बाध्य है कि इच्छुक खरीदार को परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों के संबंध में सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करना चाहिए, जिसमें बोझ भी शामिल है।

चीजों की योग्यता में, हम आधिकारिक परिसमापक को कंपनियों की संपत्तियों की परिसमापन में बिक्री के भविष्य के नोटिसों को उसी तरह और व्यापक भाषा में जारी करने का निर्देश देना आवश्यक समझते हैं जैसा कि शीर्ष अदालत के फैसले से बचने के लिए ऊपर उद्धृत किया गया है।

जटिलताएँ"।

9. सामान्य निर्णय और

दिनांकित 05.02.2009 आदेश से व्यथित

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इस प्रकार पारित, अपीलार्थी ओ. एल. ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है। 9.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि कानून के लागू प्रावधानों के सही संचालन में, अपीलार्थी नहीं हो सकता है

परिसमापन पूर्व लेनदारों के ब्याज और पात्रता की अवहेलना करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर परिसमापन के बाद के दावों के लिए उत्तरदायी बनाया गया। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने परिसमापन से पहले के दावों को स्वीकार किया है और कंपनी अधिनियम की धारा 530 के अनुसार परिसमापन के बाद के दावों को सही ढंग से खारिज कर दिया है, क्योंकि श्रमिकों/कर्मचारियों को सेवा से छुट्टी दे दी गई थी। अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियाँ और संपत्तियाँ न्यायालय की अभिरक्षा में मानी जाती हैं और अपीलार्थी ने कोई व्यवसाय नहीं किया है और न ही लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी के परिसमापन के बाद पानी का उपयोग

किया है। 9.2 . विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय परिसमापन के बाद की देनदारियों को आधिकारिक समकक्ष के रूप में मानने में उचित नहीं था।

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

9.3 . यह भी तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कभी भी अपने बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कदम नहीं उठाए, जैसा कि इसमें दावा किया गया है। ऋण के प्रमाण के अपने शपथ-पत्र और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर परिसमापन के बाद के दावे के दायित्व को निर्धारित करने से पहले इस तरह के शपथ-पत्र पर विचार भी नहीं किया।

9.4 . विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को दिए गए लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया जाना चाहिए था

कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के नियम और शर्तें

परिसमापन। विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि निविदाकारों/बोलीदाताओं को परिसंपत्तियों से संबंधित सभी प्रासंगिक पहलुओं के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा, जब उन्हें "जैसा कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है और इसलिए, खरीददार को परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों को खरीदने से पहले दोषों, बोझ और वैधानिक बकाया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। विद्वान वकील इस बात पर जोर देंगे कि जब बिक्री के नियमों और शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिसंपत्तियों की बिक्री "जहां कुछ भी है" के आधार पर होगी, तो ऐसी शर्तों पर संपत्ति खरीदने के बाद, खरीदार संपत्ति के स्वामित्व या विवरण में दोष के आधार पर कीमत में कमी के संबंध में कोई दावा करने का हकदार नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय के आदेशों के तहत ओ. एल. द्वारा किसी कंपनी की संपत्ति को परिसमापन में बेचने का मामला किसी व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति बेचने के मामले से पूरी तरह से अलग है।

स्वयं। रिलायंस को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (ऊपर), हरियाणा वित्तीय निगम बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया है। राजेश गुप्ता: (2010) 1 एस. सी. सी. 655; यू. टी. चंडीगढ़ प्रशासन और ए. एन. आर. वी. अमरजीत सिंह और ओआरएस। : (2009) 4 एस. सी. सी. 660; और पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण बनाम। रघु नाथ गुप्ता: (2012) 8 एससीसी 197।

10. अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों का अनिवार्य रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2, इस्पात प्राधिकरण की ओर से समर्थन किया गया है।

इंडिया लिमिटेड, परिसमापन में कंपनी के लेनदारों में से एक, जिसने अपनी सहायक आईआईएससीओ लिमिटेड के साथ दावा दायर किया है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उच्च [2023] 7 एस. सी. आर. के निष्कर्ष।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय बिक्री सूचना में निष्कासन खंडों से संबंधित बिंदु पर कानून से सहमत नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री "जो कुछ भी है उसके आधार पर" थी। यह तर्क दिया गया है कि नीलामी खरीदार संपत्ति को स्वामित्व के सभी दोषों के अधीन लेता है और कैविएट एम्टर का सिद्धांत सीधे लागू होता है। ऐसे खरीदार को। अहमदाबाद नगर निगम बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। हाजी अब्दुल गफूर हाजी हुसैनभाई: (1971) 1 एस. सी. सी. 757 पर भरोसा किया गया है।

11. कॉन्ट्रा के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने

जिसे अपीलार्थी ओ. एल. द्वारा अपनी अभिरक्षा में रहते हुए संपत्ति को बनाए रखने के लिए भुगतान किया जाना था और इसलिए, दायित्व को कंपनी की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त मूल्य से पूरा किया जाना है। इस संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि 1959 के नियमों के नियम 338 के संदर्भ में, ओ. एल. द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों को "संरक्षित करने, प्राप्त करने या प्राप्त करने" के लिए किए गए खर्चों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है और उक्त नियम में इसके बाद अन्य लागतों और देय खर्चों के संबंध में वरीयता के क्रम का प्रावधान है।

कंपनी की परिसंपत्तियाँ।

11.2 . विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि वरीयता

कंपनी अधिनियम की धारा 530 में निर्धारित भुगतान उसके तहत निर्दिष्ट दावों के भुगतान के लिए हैं और वह भी समापन की लागतों और खर्चों के भुगतान के बाद जो अपीलार्थी द्वारा उचित रूप से किए जाते हैं और

जिनका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उक्त धारा 530 परिसमापन से पहले की अवधि के दावों से संबंधित है, जिसके लिए प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है, लेकिन उक्त प्रावधान में परिसमापन के बाद की अवधि के दौरान ओएल द्वारा किए गए खर्चों के लिए कोई आवेदन नहीं है, जिन्हें प्राथमिकता में भुगतान करने की आवश्यकता है। परिसमापन के बाद के खर्चों से संबंधित देयता और प्राथमिकता के संबंध में, कुछ अंग्रेजी निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है, जिसमें इन री तोशोकू फाइनेंस यूके पीएलसी शामिल है: [2002] 1 डब्ल्यूएलआर 671।

11.3 . प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील ने मजबूत रखा है

1956 के एम. पी. अधिनियम की धारा 185 पर यह प्रस्तुत करने के लिए निर्भरता कि यह प्रावधान भूमि और भवन के साथ-साथ चल संपत्तियों पर भी पहले शुल्क के रूप में नगरपालिका करों का भुगतान करने का दायित्व पैदा करता है और परंतुक आधिकारिक समतुल्य v.

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि कर का बकाया किसी भी अधिभोगकर्ता से वसूली योग्य नहीं है जो मालिक नहीं है, यदि बकाया उस अवधि का है जब ऐसा अधिभोगकर्ता कब्जे में नहीं था। इसलिए, परंतुक को देखते हुए, नीलामी बिक्री की पुष्टि से पहले की अवधि के लिए कर की बकाया राशि, नीलामी खरीदार से वसूल नहीं की जा सकती है और इसे ओ. एल. द्वारा भुगतान किया जाना है।

11.4 . यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 520 के संदर्भ में, नगरपालिका करों का दावा किया जाना चाहिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को समाप्त करने की लागत होगी; और अपीलार्थी परिसंपत्तियों के कब्जे में होने के कारण, नगरपालिका करों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जो संपत्ति की रक्षा और संरक्षण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए था।

12. प्रत्यर्थी संख्या 3-नीलामी खरीदार-के विद्वान वकील ने इन प्रस्तुतियों के साथ आक्षेपित आदेशों का विधिवत समर्थन किया है कि वर्तमान मामले में कर बकाया "परिसमापन के बाद का बकाया" था जो "परिसमापन की लागत" के बराबर था और इसे अकेले ओ. एल. द्वारा वहन किया जाना था और नीलामी खरीदार पर थोपा नहीं जा सकता था।

12.1 . प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि नीलामी खरीदार अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि की तारीख से संपत्ति कर और जल कर के लिए उत्तरदायी है, यानी उसने ऐसे सभी दावों का निपटारा कर दिया है, लेकिन फिर, बिक्री की पुष्टि की तारीख से पहले करों के लिए उस पर कोई दायित्व नहीं है जब कंपनी की संपत्ति कानूनी रूप से वैध थी और ओ. एल. के हाथों में थी।

12.2 . इसके अलावा, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि कंपनी अधिनियम और 1959 के नियम खरीदार पर बकाया का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं लगाते हैं जो समापन के आदेश की तारीख और बिक्री की पुष्टि की तारीख के बीच की अवधि से संबंधित है। वर्तमान मामले में दावे परिसमापन के बाद के शुल्क या लागत हैं और इसलिए, परिसमापन के खर्च हैं, जो परिसमापन की आय से वहन किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, यदि कोई हो; और इस हद तक कि वे परिसमापन की आय समाप्त होने के बाद अवैतनिक रहते हैं, को कम करना है। इस संबंध में, उक्त निर्णय, इन रे तोशोकू फाइनैस यूके पीएलसी पर निर्भरता रखी गई है।

12.3 . विद्वान वकील ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 9 की धारा 100 के साथ-साथ अहमदाबाद में इस न्यायालय के फैसलों का भी उल्लेख किया है।

नगर निगम (उपरोक्त) और ए. आई. चम्पदानी लिमिटेड v. आधिकारिक परिसमापक और एएनआर। : (2009) 4 एस. सी. सी. 486 यह प्रस्तुत करने के लिए कि नीलामी खरीदार को बिना किसी सूचना के और बिक्री के संदर्भ में किसी भी प्रावधान या किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में कर के ऐसे बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है; और

9 इसके बाद इसे '1882 का अधिनियम' भी कहा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि हाथ में किसी भी संपत्ति के खिलाफ कोई आरोप लागू नहीं किया जा सकता है हस्तांतरणकर्ता को विचार के लिए और आरोप की सूचना के बिना; और यह कि इसकी प्रवर्तनीयता के लिए, कानून के एक प्रावधान को स्पष्ट रूप से हस्तांतरणकर्ता के हाथों में संपत्ति के खिलाफ आरोप को लागू करने के लिए प्रावधान करना चाहिए, बिना आरोप को सूचित किए और केवल आरोप नहीं बनाना चाहिए। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि 1956 के उक्त एम. पी. अधिनियम के संदर्भ में नगरपालिका करें के संबंध में बकाया संपत्ति पर कोई बोझ या शुल्क पैदा नहीं करता है जैसे कि हर समय और सभी परिस्थितियों में संपत्ति के साथ चलना जैसा कि ए. आई. चम्पदानी लिमिटेड (ऊपर) में आयोजित किया गया है। इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोई बोझ है जो संपत्ति के मूल्य को कम करता है।

12.4 . यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा कोई दायित्व नहीं है जो

विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि ऐसी शर्त एक संपत्ति के भौतिक गुणों से संबंधित है और इसे आरोप या बोझ की रचनात्मक सूचना के संकेत के रूप में नहीं माना जा सकता है। अहमदाबाद नगर निगम (ऊपर) पर भरोसा रखा गया है, जिसने बदले में, नगर बोर्ड, कानपुर बनाम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के तर्क को मंजूरी दे दी है। रूप चंद जैन और अन्न। : एयर 1940 ऑल 456।

12.5 . यह संतुष्ट किया गया है कि 1956 के एम. पी. अधिनियम की धारा 185 के आधार पर, बकाया का दावा केवल उस व्यक्ति से किया जा सकता है जो

प्रासंगिक समय पर एक अधिभोगकर्ता और किसी और से नहीं और इसलिए, नीलामी खरीदार द्वारा कोई पूछताछ करने या उस पर कोई रचनात्मक जानकारी थोपने का सवाल नहीं उठता है; बल्कि, धारा 185 का प्रावधान नीलामी खरीदार को ऐसे कर बकाया के बारे में पूछताछ करने से भी मुक्त करता है। इस संबंध में, दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम में निर्णय पर और अधिक निर्भरता रखी गई है। केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। : (2016) 13 एससीसी 561।

12.6 . अंत में, विद्वान वकील ने इस पर भरोसा रखा है

प्रत्यर्थी सं. 3 और अपीलार्थी के बीच पत्राचार, अपीलार्थी के पास आधिकारिक समतुल्य का निर्वहन करने के लिए उपलब्ध निधियों की पर्याप्तता का सुझाव देने के लिए।

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

शेयरधारकों को किसी भी बची हुई राशि को वितरित करने से पहले प्रतिवादी संख्या 1 के दावे।

13. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और

अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

14. ऊपर जो ध्यान दिया गया है, उसके लिए अपीलार्थी ओ. एल. और प्रत्यर्थी संख्या 1 निगम के बीच विवाद, संक्षेप में कहें तो,

10.07.1997 (जिस तारीख को कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया था) और 04.07.2003 (जिस तारीख को खरीदार के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की गई थी) के बीच की अवधि के लिए दरों और करों को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि देखा गया है, 10.07.1997 से 04.07.2003 के बीच की अवधि के संबंध में अपीलार्थी OL द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 निगम के दावे की आंशिक अस्वीकृति को कंपनी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि परिसमापन के बाद की देनदारियों को परिसमापन में कंपनी को समाप्त करने की लागत के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए और इस तरह की देनदारियों को कंपनी की अन्य सभी देनदारियों पर प्राथमिकता मिलेगी। कंपनी न्यायालय ने कहा और दोहराया कि कुछ लेनदारों की प्राथमिकता का सिद्धांत कंपनी के समापन के आदेश के पारित होने के समय कंपनी के दायित्व पर लागू होगा, लेकिन समापन में कंपनी की ओर से की गई लागत और खर्च का पूरा भुगतान किया जाना था।

और दरों और करों का भुगतान करने के लिए कंपनी का दायित्व बंद करने के आदेश के साथ स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होगा। कंपनी न्यायालय ने अभी तक अपीलकर्ता ओ. एल. के लिए 1956 के एम. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील दायर करने के लिए खुला छोड़ दिया है, यह देखते हुए कि जब तक ऐसी अपील दायर नहीं की जाती है और मांग को कम नहीं किया जाता है, तब तक अपीलकर्ता ओ. एल. निगम के दावे के अनुसार परिसमापन के बाद की अवधि के लिए भी कर देयता का निर्वहन करने के लिए बाध्य है। प्रभाग के समक्ष अपीलार्थी का विवाद कंपनी न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को चुनौती देने वाली पीठ अनिवार्य रूप से बिक्री के नियमों और शर्तों के संदर्भ में थी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (उपरोक्त) में निर्णय पर निर्भर थी। डिवीजन बेंच ने उद्धृत निर्णय में बिक्री के नियमों और शर्तों और वर्तमान मामले में बिक्री के नियमों और शर्तों की तुलना की और कहा कि वर्तमान मामले में बिक्री सूचना समान और व्यापक भाषा में नहीं दी गई थी ताकि प्रतिवादी संख्या 3 को ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सके।

परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में, यदि कोई देनदारियाँ हैं, तो वे स्वयं जानते हैं। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि

कंपनी अधिनियम की धारा 530 का उन करों के संबंध में कोई अनुप्रयोग नहीं था जो परिसंपत्तियों को बंद करने के आदेश की तारीख और परिसंपत्तियों की बिक्री की तारीख के बीच हो सकते हैं। इसी तरह, डिवीजन बेंच ने संकेत दिया [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके संबंधित स्टैंड पर थोड़ा विस्तार के साथ। अप्रासंगिक पहलुओं को एक तरफ छोड़ते हुए, साफ सवाल यह है कि क्या परिसमापन के बाद की अवधि से संबंधित संपत्ति कर और जल कर के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 निगम द्वारा किए गए दावे, समापन के आदेश की तारीख से और नीलामी खरीदार को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तारीख तक, अपीलकर्ता ओ. एल. के खिलाफ स्वीकार्य हैं। 15. प्रश्न से निपटने के लिए, हम वर्तमान मामले से संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर उपयोगी रूप से ध्यान दे सकते हैं।

15.1 . कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए और धारा 530 के प्रासंगिक भागों को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है: -

" 529ए. तरजीही भुगतान को ओवरराइड करना। - इसके बावजूद इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के किसी अन्य प्रावधान में निहित कुछ भी, किसी कंपनी के समापन में

(क) कामगारों का बकाया; और

(बी) प्रतिभूत लेनदारों को देय ऋण इस हद तक कि ऐसे ऋण धारा की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (सी) के तहत श्रेणीबद्ध हैं।

529 इस तरह के बकाया के साथ,

अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा।

530. तरजीही भुगतान। - (1) धारा 529क के प्रावधानों के अधीन रहते हुए समापन में सभी को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अन्य ऋण

(क) उप-धारा (8) के खंड (ग) में परिभाषित सुसंगत तिथि पर कंपनी से केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी राजस्व कर, उपकर और दरें।

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

और बारह महीनों के भीतर देय और देय हो गया है

उस तारीख से पहले अगला;

(8) इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(ए)।

(ग) "सुसंगत तिथि" पद का अर्थ है
जिसे बंद करने का आदेश दिया गया है

(i) एक कंपनी के मामले में

अनिवार्य रूप से नियुक्ति की तारीख (या पहली नियुक्ति)

किसी अस्थायी परिसमापक की, या यदि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी,

समापन आदेश की तारीख, जब तक कि किसी भी मामले में

कंपनी को पहले स्वेच्छा से बंद करना शुरू कर दिया गया था।

उस तारीख को; और

((ii) किसी भी मामले में जहां उपखंड (i) लागू नहीं होता है,

स्वैच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित करना

कंपनी ने।

*** "

15.2 . कंपनी (न्यायालय) नियमों के नियम 154,163 और 338,

ये निम्नानुसार हैं: -

" R.154। ऋणों का मूल्य-सभी ऋणों और उनके विरुद्ध दावों का मूल्य।

कंपनी का अनुमान, जहाँ तक संभव हो, के अनुसार लगाया जाएगा - समापन के क्रम की तारीख पर इसका मूल्य -

कंपनी या जहाँ याचिका प्रस्तुत करने से पहले

समापन के लिए, कंपनी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है स्वैच्छिक समापन-इस तरह के प्रस्ताव के पारित होने की तारीख पर।

R.163। सूचित किए जाने वाले प्रमाण की स्वीकृति या अस्वीकृति

- ऐसी जाँच के बाद जो वह आवश्यक समझे, परिसमापक

लिखित रूप में सबूत को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करेगा। प्रत्येक परिसमापक का किसी प्रमाण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय, या तो

पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संबंधित लेनदार को सूचित किया जाएगा। पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत डाक द्वारा जहां प्रमाण स्वीकार किया जाता है

और स्वीकृति के लिए पंजीकृत डाक द्वारा जहां प्रमाण [2023] 7 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया, बशर्ते कि किसी ऐसे लेनदार को दावा स्वीकार करने की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा जो परिसमापक के सामने पेश हुआ हो और जिसके दावे की स्वीकृति के बारे में उसे या उसके एजेंट को स्वीकृति के समय लिखित रूप में सूचित किया गया हो। जहां परिसमापक किसी प्रमाण को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार करता है, वह ऋणदाता को अस्वीकार करने का आधार प्रपत्र No.69 में बताएगा, प्रमाण के प्रवेश की सूचना प्रपत्र No.70 में होगी।

R.338। परिसंपत्तियों में से न्यायालय द्वारा परिसमापन में देय लागत और व्यय।

(1) परिसमापन में एक कंपनी की परिसंपत्तियाँ-न्यायालय द्वारा

परिसंपत्तियों को संरक्षित करने, प्राप्त करने या प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए शुल्क और खर्चों के भुगतान के बाद शेष, जिसमें वे भी शामिल हैं, जहां कंपनी पहले समाप्त होने लगी है।

स्वैच्छिक रूप से, ऐसा पारिश्रमिक, लागत और व्यय जो न्यायालय परिसमापक को इस तरह के स्वैच्छिक समापन में अनुमति दे, न्यायालय के किसी भी आदेश और सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए निम्नलिखित भुगतानों के लिए उत्तरदायी होंगे जो प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में किए जाएंगे, अर्थात्: सबसे पहले। - याचिका पर उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति की कर लागत सहित याचिका की कर लागत, जिसके खर्च की अनुमति है

अदालत।

इसके बाद। - किसी भी व्यक्ति की लागत और व्यय जो कंपनी के मामलों का विवरण बनाता है या बनाने में सहमत होता है;

इसके बाद। - कंपनी की संपत्तियों को संरक्षित करने, प्राप्त करने या प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए खर्चों के अलावा आधिकारिक परिसमापक का आवश्यक संवितरण;

इसके बाद। - आधिकारिक परिसमापकों द्वारा उचित रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति की लागत; इसके बाद। - धारा 451 (2) के तहत सरकार को जमा की जाने वाली फीस;

इसके बाद। - निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से किए गए और न्यायालय द्वारा स्वीकृत वास्तविक व्यय।

आधिकारिक समकक्ष v. उज्जैन नगर पालिका निगम

& ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(2) अदालत द्वारा अन्यथा आदेश दिए गए अनुसार बचत करें, इस संबंध में कोई भुगतान नहीं अधिवक्ताओं के बिलों को कंपनी की परिसंपत्तियों से इस प्रमाण के बिना अनुमति दी जाएगी कि उन पर विचार किया गया है और

न्यायालय के कर अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई। कर अधिकारी किसी अधिवक्ता के विधेयकों या प्रभारों को पारित करने से पहले खुद को संतुष्ट करेगा कि परिसमापक को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक अधिवक्ता की नियुक्ति को विधिवत मंजूरी दी गई है।

(3) इस नियम में निहित कुछ भी उन लागतों पर लागू या प्रभावित नहीं होगा जो कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के दौरान होती हैं।

जिसे न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा रहा है, उस न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है जिसमें ऐसी कार्यवाही लंबित है, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना है।

या परिसमापक, या उस व्यक्ति के अधिकार जिसके लिए ऐसी लागतें आती हैं

देय हैं। "

15.3 . मध्य प्रदेश नगर निगम की धारा 185

अधिनियम, 1956, जिस पर चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया जाता है, निम्नानुसार है:

किसी भी भूमि या भवन पर करों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से देय सभी राशियां, सरकार को देय किसी भी भूमि राजस्व के पूर्व भुगतान के अधीन रहते हुए, उक्त भूमि या भवन पर और ऐसी भूमि या भवन के भीतर या उस पर पाई जाने वाली किसी भी चल संपत्ति पर और उक्त व्यक्ति से संबंधित पहली प्रभार होगी। बशर्ते कि ऐसे किसी भी कर का कोई बकाया किसी भी अधिभोगकर्ता से वसूल करने योग्य नहीं होगा जो मालिक नहीं है, यदि ऐसे बकाया किसी के लिए हैं।

वह अवधि जिसके दौरान कब्जा करने वाला कब्जे में नहीं था।

16. इसमें निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रमुख बिंदुओं में से एक

मामला प्रत्यर्थी संख्या 3 को परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री का प्रभाव और प्रभाव है, विशेष रूप से जब संपत्ति को "जैसा है जैसा भी है" के आधार पर बेचा गया था। अपीलार्थी के

विद्वान वकील ने अपने इस तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के कुछ फैसलों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है कि बिक्री के नियमों और शर्तों को देखते हुए, खरीदार को दोषों, बोज़ों और वैधानिक बकाया के बारे में पूरी जानकारी होगी और ऐसे बकाया के प्रति उत्तरदायी रहेगा, विशेष रूप से जब वर्तमान मामले में बिक्री अदालत के आदेशों के तहत अपीलार्थी ओएल द्वारा की गई थी। इसके विपरीत, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने यह दावा करने के लिए कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है कि [2023] 7 एस. सी. आर. में संपत्ति के खिलाफ कोई आरोप लागू नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुल्क की सूचना के बिना विचार के लिए हस्तांतरणकर्ता के हाथ और नगरपालिका करों के लिए, जो विचाराधीन संपत्ति पर बोझ या शुल्क पैदा नहीं करते हैं। हम अनुपात निर्णय और उसमें उपलब्ध सिद्धांतों पर ध्यान देने के लिए उद्धृत निर्णयों की बारीकी से जांच कर सकते हैं।

17. अपीलार्थी ओ. एल. की ओर से प्रस्तुतियों का शीट एंकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है।

(उपर्युक्त) जो इस प्रस्ताव के लिए उद्धृत किया गया है कि परिसमापन में कंपनी की संपत्ति और परिसंपत्तियों की बिक्री में, आधिकारिक परिसमापक उसके संबंध में कोई गारंटी या वारंटी नहीं रखता है; और खरीदार को हर मामले में खुद को संतुष्ट करना पड़ता है, विशेष रूप से बोझ के संबंध में। इसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की: -

" 14. जब आधिकारिक परिसमापक संपत्ति और परिसंपत्तियाँ बेचता है न्यायालय के आदेशों के तहत परिसमापन में एक कंपनी का वह नहीं कर सकता है

और इसके संबंध में कोई गारंटी या वारंटी नहीं रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे परिसमापन में कंपनी के रिकॉर्ड से जो पता चलता है, उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। यह इच्छुक खरीदार के लिए है कि वह अचल संपत्ति के स्वामित्व, बोझ आदि के बारे में हर तरह से खुद को संतुष्ट करे जिसे वह खरीदने का प्रस्ताव करता है। वह ऐसी शर्तों पर संपत्ति खरीदने के बाद संपत्ति के स्वामित्व या विवरण में दोष के आधार पर कीमत में कमी का दावा नहीं कर सकता है। आदेशों के तहत परिसमापन में एक कंपनी की संपत्ति बेचने वाले आधिकारिक परिसमापक का मामला

न्यायालय का मामला किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अचल संपत्ति बेचने के मामले से पूरी तरह से अलग है। इसलिए, त्रिपुति की ओर से किए गए आवेदन में कोई योग्यता नहीं है कि

कीमत में कमी होनी चाहिए या इसे उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए

1 करोड़ 98 लाख रुपये की राशि पर ब्याज का भुगतान करना।

17.1 . पहली बार में, उक्त निर्णय ऐसा प्रतीत हो सकता है

वर्तमान मामले के तथ्यों के करीब कहीं खड़े होने के कारण, यह भी एक ओ. एल. द्वारा कुछ हद तक समान शर्त के साथ परिसंपत्तियों की बिक्री का मामला था कि बिक्री "जैसा है वैसा ही है" के आधार पर थी। हालाँकि, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सही बताया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ

इंडिया (उपरोक्त) और वर्तमान मामले के मामले में बिक्री के नियमों और शर्तों में उल्लेखनीय अंतर था।

17.2 . जैसा कि आक्षेपित निर्णय में देखा और निकाला गया है

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ (उपर्युक्त), बिक्री सूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक महत्वपूर्ण शर्त थी जिसके तहत खरीदार को "आधिकारिक समकक्ष के रूप में सभी मामलों में" खुद को संतुष्ट करने के लिए सूचित किया गया था।

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

चल और अचल संपत्तियों को उनके स्वामित्व, बोझ, क्षेत्र, सीमा, विवरण, गुणवत्ता, मात्रा और मात्रा आदि के रूप में माना जाता है। इसमें यह भी कहा गया था कि "खरीदार किसी भी खाते में किसी भी मुआवजे या कीमत में कटौती का हकदार नहीं होगा और माना जाएगा कि उसने संपत्ति खरीदी है।

श्रम, कर्मचारी आदि को प्रभावित करने वाले मौजूदा कानून के तहत सभी बाधाओं, पूर्वाधिकारों और दावों के लिए। इस तरह की शर्तों ने संयोग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और न ही किसी अस्पष्टता के लिए जहां खरीदार को न केवल भौतिक विशेषताओं के बारे में खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता थी परिसंपत्तियों के साथ-साथ सभी बोझ, पूर्वाधिकार और दावों के बारे में भी। दुर्भाग्य से, वर्तमान मामले में बिक्री के नियम और शर्तें ऐसी भौतिक शर्तों से बहुत कम थीं।

17.3 . हमने वर्तमान मामले में दिनांकित 09.05.2003 की बिक्री सूचना की सामग्री और प्रासंगिक शर्तों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया है और

परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री की शर्तें। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ओ. एल. द्वारा वर्तमान मामले में बिक्री के नियमों और शर्तों में विस्तृत तकनीकी अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया था कि यह "जैसा है, जो कुछ भी है" के आधार पर होगा और फिर, आगे का अस्वीकृति कहा गया था कि अपीलार्थी ओ. एल. कोई भी प्रावधान प्रदान नहीं कर रहा था।

बेची गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, मात्रा या विनिर्देशन के बारे में गारंटी।

इस तरह की शर्तों और अस्वीकृतियों ने निश्चित रूप से खरीदारों को सूचित किया कि संपत्ति क्या है (प्रकृति और विस्तार); संपत्ति कहाँ है (स्थानीय विशेषताएँ); और जो कुछ भी है (संपत्ति की मात्रा और स्थिति)। बोली लगाने वालों/खरीदारों को परिसंपत्तियों के भौतिक निरीक्षण के बाद प्रकृति, विस्तार, स्थान, मात्रा और गुणवत्ता के पहलुओं के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के लिए आगे चेतावनी दी गई थी और यह भी सूचित किया गया था कि उन्हें विवरण में दोष, यदि कोई हो, के बारे में पूरी जानकारी के साथ पेशकश करने के लिए माना जाएगा।

बेची गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता या मात्रा। इस तरह की सभी शर्तें अनिवार्य रूप से विचाराधीन परिसंपत्तियों की भौतिक संपत्तियों/विशेषताओं से संबंधित थीं, लेकिन उन नियमों और शर्तों में महत्वपूर्ण चूक यह थी कि बोली लगाने वाले/खरीदार पर खुद को बोझ, ग्रहणाधिकार और संबंधित परिसंपत्तियों से जुड़े दावों के बारे में जागरूक करना अनिवार्य था। यह चूक अपीलार्थी के मामले की जड़ पर प्रहार करती है।

17.4 . उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ठीक ही कहा है कि यदि इच्छुक खरीदार को हर तरह से खुद को संतुष्ट करना आवश्यक था

अड़चनों सहित, हो सकता है कि उन्हें अड़चनों के बारे में जानकारी के अभाव के बारे में किसी भी आपत्ति में नहीं सुना जाए, लेकिन अगर उन्हें इस तरह की चेतावनी नहीं दी गई थी, तो ऐसे [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खुद को बाधाओं के बारे में जागरूक करने का दायित्व किसी भी काल्पनिक कल्पना द्वारा थोपा नहीं जा सकता है।

18. हरियाणा वित्तीय निगम में इस न्यायालय का निर्णय

(उपर्युक्त) को यह प्रस्तुत करने के लिए भी उद्धृत किया गया है कि ओ. एल. के पास बेची गई संपत्ति के संबंध में कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। उक्त मामले में, अपीलकर्ता वित्तीय निगम ने विभिन्न इकाइयों की बिक्री के लिए एक विज्ञापन जारी किया था और प्रतिवादी उन बोलीदाताओं में से एक था जिन्होंने रुपये की राशि की पेशकश की थी। 50 लाख, और रुपये जमा किए। 2.5 बकाया राशि के रूप में एक लाख। भूमि पर रास्ते की उपस्थिति को लेकर कुछ विवाद था। अपीलार्थी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण, प्रत्यर्थी ने अतिरिक्त धन जमा नहीं किया। अपीलार्थी ने नई निविदाएँ आमंत्रित कीं और प्रत्यर्थी द्वारा जमा किए गए धन को जब्त कर लिया। प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ज़ब्ती को रद्द कर दिया और 12 प्रतिशत ब्याज और रु। 5,000 लागतें। इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलार्थी वित्तीय निगम की ओर से प्रस्तुतियों में से एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (उपरोक्त) में उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में थी। उक्त निर्णय को अलग करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि आधिकारिक परिसमापक परिसमापन में कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर आगे बढ़ेगा और इसलिए, यह इरादे के लिए था

खरीदार जिस अचल संपत्ति को खरीदने का इरादा रखता है, उसके स्वामित्व, बोझ आदि के बारे में हर तरह से खुद को संतुष्ट करे। और वह खरीदार ऐसी शर्तों पर संपत्ति खरीदने के बाद, संपत्ति के स्वामित्व या विवरण में दोष के आधार पर कीमत में कमी का दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता वित्तीय निगम संपत्ति बेचने में एक मालिक के अधिकारों का प्रयोग कर रहा था और एक आधिकारिक परिसमापक के रूप में संपत्ति नहीं बेच रहा था; और अदालत के आदेशों के तहत संपत्ति बेचने वाले एक आधिकारिक परिसमापक पर लागू सिद्धांत उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो अपनी अचल संपत्ति बेच रहा है। इसके अलावा, अदालत ने कहा

उस प्रत्यर्थी ने उसमें सभी आवश्यक पूछताछ की और यह निगम ही था जो बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति का उचित विवरण देने में विफल रहा। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की: -

" 23. हमारी राय में, अपीलार्थियों को विज्ञापन के खंड 5 का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी निगम ऐसा नहीं कर सकता है

अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति दी जाए। खंड 5 निस्संदेह जमा की गई बकाया राशि को ज़ब्त करने की अनुमति देता है। लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब नीलामी-खरीदार

बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है। हमारी राय में, प्रत्यर्थी वित्तीय समकक्ष v में विफल नहीं हुआ है।

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

बिक्री की शर्तों का पालन करना। बल्कि, यह अपीलार्थी निगम है जिसने अनुचित तरीके से काम किया है, और लेने की कोशिश कर रहा है

अपनी गलती का लाभ उठाएँ"।

" 24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी निगम को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 55 पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी

निगम प्रत्यर्थी को स्वतंत्र 3 "करम" मार्ग के अस्तित्व के बारे में भौतिक दोष का खुलासा करने में विफल रहा।

संपत्ति के लिए। इसलिए, अपीलार्थी निगम ने स्पष्ट रूप से संपत्ति हस्तांतरण की धारा 55 (1) (ए) और (बी) का उल्लंघन किया। अधिनियम, 1882।

***** **

(आधिकारिक परिसमापक मामला [(1994) 1 एस. सी. सी. 575], एस. सी. सी. पी. 584 , पैरा 14)
" 14. अदालत के आदेश के तहत परिसमापन में एक कंपनी की संपत्ति बेचने वाले आधिकारिक परिसमापक का मामला

यह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अचल संपत्ति बेचने के मामले से पूरी तरह से अलग है।

उपरोक्त अवलोकन निगम पर स्पष्ट रूप से लागू होगा क्योंकि यह [2023] 7 एस. सी. आर. को बेचने में मालिक के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति। अपीलार्थी निगम इस रूप में संपत्ति नहीं बेच रहा है

एक आधिकारिक परिसमापक "।

परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री, बिक्री सूचना में बुनियादी शर्तों को बताने के कर्तव्य से मुक्त है। 19. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने

उत्तरदाताओं की उपभोक्ता शिकायतों पर विचार किया जो यह तर्क देने के लिए दायर की गई थीं कि

विज्ञापन के माध्यम से नीलाम किए गए आवासीय और वाणिज्यिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए अपीलार्थी कानूनी रूप से प्रीमियम या वार्षिक किराए की शेष राशि का दावा करने का हकदार नहीं था। इस न्यायालय ने अपीलार्थी को स्वीकार कर लिया क्योंकि मौजूदा स्थलों की सार्वजनिक नीलामी के संदर्भ में खरीदार उपभोक्ता नहीं था। इसके बावजूद, यह देखा गया कि नीलामी के संबंध में "जैसा है, जहां आधार है" के अनुसार:

" 19 साइटों की सार्वजनिक नीलामी में स्थिति पूरी तरह से अलग होती है। इच्छुक व्यक्ति प्रस्तावित साइटों का निरीक्षण कर सकता है और उस साइट का चयन कर सकता है जिसे वह हासिल करना चाहता है और केवल ऐसी साइट के संबंध में नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी में बोली लगाने से पहले, वह साइट की स्थिति और स्थिति को जानता है या पता लगाने की स्थिति में है। वह सुविधाओं के अस्तित्व या कमी के बारे में जानता है।

नीलामी "जैसा है-कहाँ है" के आधार पर होती है। इस तरह के ज्ञान के साथ, वह नीलामी में भाग लेता है और एक विशेष बोली की पेशकश करता है। इस बात की कोई बाध्यता नहीं है कि वह एक विशेष कीमत की पेशकश करे। जब

नीलाम की गई साइटें मौजूदा साइटें हैं, बिना किसी आश्वासन के /

सुविधाओं से संबंधित प्रतिनिधित्व, सेवा की कमी या सेवा से इनकार का कोई सवाल ही नहीं है। जहाँ बोलीदाता के पास स्थल और मूल्य के संबंध में विकल्प और विकल्प होता है और जब आधिकारिक प्रतीक होता है v.

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

किसी भी सुविधा या सुविधा का कोई आश्वासन नहीं, साइट के मालिक के सेवा प्रदाता बनने का सवाल एलडीए [(1994) 1 एससीसी 243] या बलबीर में निर्धारित परीक्षणों को लागू करने से भी नहीं उठता है।

सिंह [(2004) 5 एससीसी 65]।

20. जहाँ किसी विशेष आश्वासन के बिना सार्वजनिक नीलामी होती है। या विशेष सुविधाएं, और संभावित खरीदार/पट्टेदार साइट की जांच करने का अवसर मिलने के बाद नीलामी में भाग लेता है, नीलामी में बोली साइट की मौजूदा स्थिति, स्थिति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अगर सभी सुविधाएं हैं

उपलब्ध होने पर, वह अधिक राशि की पेशकश करेगा। यदि कोई सुविधाएं नहीं हैं, या यदि साइट को कोई नुकसान होता है, तो वह एक प्रस्ताव देगा

कम राशि, या नीलामी में भाग नहीं ले सकते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति खुली आँखों से नीलामी में भाग लेता है, तो वह उसके बाद भाग नहीं ले सकता है। यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह कीमत/प्रीमियम की शेष राशि या विलंबित भुगतान पर निर्धारित ब्याज, या जमीनी किराए का भुगतान इस आधार पर नहीं करेगा कि साइट कुछ निश्चित नुकसान से ग्रस्त है।

नुकसान या इस आधार पर कि सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं।

19.1 . केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन का उपरोक्त मामला,

नीलामी में बेची गई संपत्ति में बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतों के संबंध में "जैसा है वैसा ही" आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है।

20. पंजाब शहरी योजना और विकास के मामले में

प्राधिकरण (ऊपर), विवाद की जड़ नीलामी के माध्यम से वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन को स्वीकार करने के बाद किशतों के विलंबित भुगतान के कारण ब्याज, दंडात्मक ब्याज और जुर्माना लगाना था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नीलामी सूचना और आवंटन पत्र की शर्तों के अधीन वाणिज्यिक भूखंडों को स्वीकार करने के बाद खरीदार इस तरह के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। -

“ 17 हम दोहरा सकते हैं कि सार्वजनिक नीलामी में वाणिज्यिक भूखंडों के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद

भुगतान की सुविधा के लिए, उत्तरदाता यह नहीं कह सकते हैं कि वे नीलामी सूचना के साथ-साथ आवंटन पत्र के नियमों और शर्तों से बाध्य नहीं हैं। तथ्यों पर भी, हमने पाया है कि प्रदान करने में पुडा की ओर से कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई थी वे सुविधाएं। "[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20.1 . पुनः पंजाब शहरी नियोजन का उपरोक्त मामला और

विकास प्राधिकरण, जिसमें विवाद की जड़ किशतों के विलंबित भुगतान के कारण दंडात्मक ब्याज और जुर्माना लगाना था, की वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है।

21. अहमदाबाद नगर निगम में इस न्यायालय का निर्णय

निगम (ऊपर) पर प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं और सहायक उत्तरदाता द्वारा भी भरोसा किया गया है। इसमें, दिवालिया होने के बाद

कार्यवाही 1949 में शुरू हुई, विचाराधीन संपत्ति की नीलामी की गई और 1954 में प्रत्यर्थी-खरीदार द्वारा खरीदी गई। यह नगर निगम द्वारा इस तथ्य के कारण कुर्क किया गया था कि 1949-50 से 1953-1955 के लिए बकाया नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया था, जिससे प्रतिवादी खरीदार को घोषणा के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा। गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संपत्ति का मालिक था और बकाया के लिए शुल्क लागू करने योग्य नहीं था, जिसे निगम ने इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। 1882 के अधिनियम की धारा 100 के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हस्तांतरणकर्ता के हाथों में किसी भी संपत्ति के खिलाफ बिना किसी सूचना के विचार के लिए कोई आरोप लागू नहीं किया जाएगा।

प्रभार, इसके अलावा जहां कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान किया गया है। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: -

" 4. यह खंड असंदिग्ध भाषा में बताता है कि कोई शुल्क नहीं है

अंतरिती के हाथों में किसी भी संपत्ति के खिलाफ प्रवर्तनीय है

शुल्क की सूचना के बिना विचार के लिए, सिवाय इसके कि वह कहाँ है अन्यथा उस समय के लिए किसी भी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया

बल देते हैं। कानून के बचत प्रावधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान होना चाहिए -

एक के हाथों में संपत्ति के खिलाफ आरोप का प्रवर्तन

शुल्क की सूचना के बिना मूल्य के लिए हस्तांतरणकर्ता और न केवल

एक शुल्क बनाएँ।

11. अब वे परिस्थितियाँ जो काल्पनिक मानी जाती हैं

एक पक्ष को नोटिस पूछताछ के लिए उसके जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर आधारित है
या

पता लगाएँ कि किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए या उसकी घोर लापरवाही पर।

नोटिस की इस धारणा को आमतौर पर रचनात्मक के रूप में जाना जाता है।

अब यह हमारे क़ानून का एक हिस्सा है और हमें इसकी व्याख्या इस तरह करनी होगी।
जानबूझकर परहेज करना सचेत या जानबूझकर परहेज करने का सुझाव देता है और

लापरवाही को आम तौर पर ऐसा करने में चूक के रूप में समझा जाता है।
परिस्थितियों में उचित देखभाल एक व्यक्ति का कर्तव्य है आधिकारिक समकक्ष v।

उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

लेने के लिए सामान्य विवेक का। दूसरे शब्दों में यह कुछ ऐसा करने के लिए एक चूक है जो एक समझदार व्यक्ति उन विचारों द्वारा निर्देशित करता है जो सामान्य रूप से मानव मामलों के आचरण को नियंत्रित करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो आम तौर पर एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति नहीं करता है। जानबूझकर अनुपस्थित रहने या घोर लापरवाही का सवाल और इसलिए, इस दृष्टिकोण से विचार किए गए रचनात्मक नोटिस का सवाल आम तौर पर तथ्य का सवाल है या तथ्य और कानून का सबसे अच्छा मिश्रित सवाल है जो मुख्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सीधे तीन स्पष्टीकरणों के भीतर आने वाले मामलों को छोड़कर, सभी संभावित आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए कोई भी कठोर नियम नहीं रखा जा सकता है। वर्तमान जैसी परिस्थितियों में जिस सवाल का जवाब देना है, वह यह नहीं है कि क्या खरीदार के पास प्राप्त करने के साधन थे और क्या उसने विवेकपूर्ण सावधानी के साथ आरोप का ज्ञान प्राप्त किया होगा, बल्कि यह है कि क्या ऐसा नहीं करने में उसने जानबूझकर परहेज किया या घोर लापरवाही से काम लिया। एक यथोचित विवेकपूर्ण व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर एक प्रश्न होने के नाते, न्यायालयों को भारतीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में इस पर विचार करना होगा। इसलिए, भारत में न्यायालयों को अंग्रेजी उदाहरणों से सहायता लेने में सावधान और सतर्क रहना चाहिए, जिनका आखं मूंदकर या बहुत आसानी से पालन नहीं किया जाना चाहिए।

21.1 . अहमदाबाद नगरपालिका के उपरोक्त मामले में

नीलामी बिक्री संपत्ति को स्वामित्व के सभी दोषों के अधीन ले जाती है और कैविएट एम्प्टर (खरीदार को जागरूक होने दें) का सिद्धांत ऐसे खरीदार पर लागू होता है, लेकिन इसके बाद, अदालत ने कहा कि फैसले का मामला-ऋणी जिसका बेची गई संपत्ति में कोई बिक्री योग्य ब्याज नहीं है, जैसा कि सिविल कोड के आदेश XXI नियम 91 द्वारा विचार किया गया है। हालाँकि, प्रक्रिया अलग थी और इस सिद्धांत में शामिल नहीं थी। इस तरह की टिप्पणियाँ अपीलार्थी के मामले का समर्थन नहीं करती हैं ताकि महत्वपूर्ण होने के बावजूद नीलामी खरीदार पर पूरा बोझ डाला जा सके।

बिक्री के नियमों और शर्तों में चूक।

22. ए. आई. चम्पदानी लिमिटेड (ऊपर) में, अपीलार्थी ने परिसमापन के तहत कंपनी की परिसंपत्तियों को खरीदा था और बाद में उसे सेवा प्रदान की गई थी। नगरपालिका द्वारा संपत्ति कर के बकाया भुगतान के लिए नोटिस के साथ। इस प्रार्थना के साथ एक कक्ष समन निकालने पर कि अपीलकर्ता केवल बिक्री की पुष्टि की तारीख के बाद संपत्ति कर के लिए उत्तरदायी होगा, आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह [2023] 7 एस. सी. आर. पर बाध्य था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्ताव देने से पहले परिसंपत्तियों से जुड़ी देनदारियों के बारे में पूछताछ करना। डिवीजन बेंच ने अदालत के भीतर की अपील को खारिज कर दिया। इस न्यायालय के समक्ष अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में नगरपालिका कर के संबंध में देय राशि

कंपनी अधिनियम संपत्ति पर बोझ या शुल्क नहीं लगाता था और इसे व्यक्तिगत दायित्व माना जाता था। यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित करता है: -

" 10. प्रावधानों के संदर्भ में नगरपालिका कर के संबंध में देय राशि

उक्त अधिनियम संपत्ति पर कोई बोझ नहीं डालता है। यह.

कोई शुल्क नहीं बनाता है। यह व्यक्तिगत माना जाता है

दायित्व। उपरोक्त आधार पर, हमें इसका अर्थ लगाना होगा बिक्री के नियम और शर्तों।

12. बिक्री के नियमों और शर्तों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

इसका एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए। शब्द "बोझ"

"अचल संपत्ति" शब्द के संबंध में एक विशिष्ट विशेषता है

अर्थ। इसे आम तौर पर एक सामान्य और/या निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।

शब्दकोश का अर्थ।

15. प्रत्यर्थी नगरपालिका एक असुरक्षित लेनदार थी। में।

कि क्षमता यह एक सामान्य से उच्च स्तर पर खड़ा नहीं हो सकता है

असुरक्षित लेनदार जिसे अन्य सभी के साथ कतार में खड़ा होना पड़ता है
समान रूप से उनके बकाया की वसूली के उद्देश्य से स्थित है

बिक्री आगे बढ़ती है।

16. कंपनी अधिनियम या कोई अन्य कानून किसी को लागू नहीं करता है।

खरीदार पर पूछताछ करने का अतिरिक्त दायित्व

उन कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए जो
उनके मूल्य में बाधा डालेंगे।

18. हम देख सकते हैं कि बॉम्बे प्रांत की धारा 141

नगर निगम अधिनियम संपत्ति कर प्रदान करता है

पहला प्रभार उस आधार पर जिसके लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें है।

अधिनियम को उसमें लागू करने में सक्षम पाया गया, जो
यह नीचे लिखा है:

आधिकारिक समकक्ष v. उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 100. शुल्क। - जहाँ एक व्यक्ति की अचल संपत्ति पक्षकारों के कार्य या कानून के संचालन द्वारा प्रतिभूति के रूप में दी जाती है दूसरे को धन का भुगतान, और लेन-देन एक बंधक के बराबर नहीं है, बाद वाले व्यक्ति को संपत्ति पर शुल्क कहा जाता है, और इसमें पहले से निहित सभी प्रावधान जो एक साधारण बंधक पर लागू होते हैं, जहां तक हो सके, ऐसे शुल्क पर लागू होंगे।

इस धारा में कुछ भी निष्पादन में ठीक से किए गए खर्चों के लिए न्यास संपत्ति पर न्यासी के प्रभार पर लागू नहीं होता है।

उसके न्यास का, और, उस समय लागू किसी कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, उस व्यक्ति के हाथों में किसी भी संपत्ति के खिलाफ कोई आरोप लागू नहीं किया जाएगा, जिसके पास ऐसी संपत्ति है।

विचार के लिए और बिना किसी सूचना के स्थानांतरित किया गया

शुल्क "। इस प्रकार, कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता है कि कानून के किसी प्रावधान को स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ आरोप को लागू करने का प्रावधान करना चाहिए।

बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए हस्तांतरणकर्ता के हाथों में संपत्ति

आरोप के लिए और न कि केवल एक आरोप बनाएँ।

23. अहमदाबाद के मामलों में उपरोक्त निर्णय

नगर निगम और ए. आई. चम्पदानी लिमिटेड बिक्री की तारीख को देय नगरपालिका करों के बकाया के लिए अदालत की बिक्री में संपत्ति की नीलामी खरीदार के दायित्व से संबंधित मुद्दे से संबंधित थे, जो बेची गई संपत्ति पर वैधानिक शुल्क के हैं और जिनमें से खरीदार को कोई सूचना नहीं थी। 1882 के अधिनियम की धारा 100 के दूसरे भाग की व्याख्या और आवेदन पर, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीलामी खरीदार को बिना किसी सूचना के, बिक्री की शर्तों या किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, इस तरह के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। वास्तव में इस स्थिति में वर्तमान मामले में, उपरोक्त सिद्धांत अपीलार्थी के मामले के खिलाफ बहुत अधिक काम करते हैं।

24. यह चुनाव लड़ने वाले की ओर से उचित तर्क दिया गया है।

प्रत्यर्थियों ने 1882 के अधिनियम की धारा 100 और ए. आई. चम्पदानी लिमिटेड (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में कहा कि किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, नीलामी खरीदार

को किसी भी शुल्क की सूचना के बिना परिसमापन के बाद की अवधि के दौरान विचाराधीन कर के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। 1956 के एम. पी. अधिनियम के प्रावधानों में संपत्ति पर ऐसा कोई बोझ या शुल्क नहीं लगाया गया था जो हर समय और सभी परिस्थितियों में संपत्ति से जुड़ा हो और न ही उन्हें ऐसा कोई बोझ कहा जा सकता है जो मूल्य (2023) 7 एस. सी. आर. को कम करता हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति से। इसके विपरीत, वे केवल कंपनी की परिसंपत्तियों को "संरक्षित करने, प्राप्त करने या प्राप्त करने" के लिए खर्च के रूप में योग्य होंगे और इस प्रकार, कंपनी की परिसंपत्तियों या उनके मूल्य के वितरण के दौरान प्राथमिकता से और किसी अन्य भुगतान से पहले भुगतान करना होगा।

25. वर्तमान मामले में एक और महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है।

कि विचाराधीन संपत्ति निर्विवाद रूप से 1956 के एम. पी. अधिनियम की धारा 185 द्वारा शासित थी, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि किसी भी भूमि या भवन पर करों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से देय सभी राशियां पहले की होंगी।

उक्त भूमि या भवन पर और ऐसी भूमि या भवन के भीतर या उस पर पाई जाने वाली किसी चल संपत्ति पर प्रभार। इसके लिए प्रावधान आगे यह स्पष्ट करता है कि ऐसे किसी भी कर का कोई बकाया किसी भी अधिभोगकर्ता से वसूल नहीं किया जाएगा जो मालिक नहीं है, यदि ऐसे बकाया उस अवधि के लिए थे जिसके दौरान अधिभोगकर्ता कब्जे में नहीं था। विचाराधीन संपत्ति पर 1956 के एम. पी. अधिनियम की उक्त धारा 185 के निर्विवाद संचालन के सामने, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि बोली लगाने वाला /

1956 के एम. पी. अधिनियम की उक्त धारा 185 के संदर्भ में अनदेखी नहीं की जा सकती है।
26. अन्य परिसमापन पूर्व लेनदारों के प्रति संभावित पूर्वाग्रह के बारे में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ यदि ऐसी परिसमापन के बाद की देनदारियों को अन्य देनदारियों पर वरीयता दी जाती है; और

कंपनी अधिनियम की धारा 529ए और 530 की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

और हस्तक्षेप के लिए कोई मामला न बनाएँ। धारा 529ए और 530 में निहित प्रावधान अनिवार्य रूप से अधिमानी वरीयता से संबंधित हैं। देय राशि के वर्गों के संबंध में भुगतान के साथ-साथ अधिमान्य भुगतान भी

उसमें निर्दिष्ट ऋण। हालांकि, इसके भुगतान का सवाल उन लागतों और समापन के खर्चों के भुगतान के बाद उत्पन्न होगा जो अपीलार्थी ओ. एल. द्वारा उचित रूप से किए जाते हैं और जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाना है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विचाराधीन अवधि के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 निगम को देय कर सीधे परिसमापन की लागत और खर्च के बराबर होंगे।

आधिकारिक समकक्ष v. उज्जैन नगर पालिका निगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपीलार्थी ओ. एल. की ओर से दोष और उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि संपत्ति कर और जल कर के कारण देयता प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी ओ. एल. द्वारा खारिज की गई सीमा तक परिसमापन के बाद का दायित्व रहा है, जिसे ओ. एल. बिक्री सूचना में चूक को देखते हुए और फिर 1959 के नियमों के नियम 338 के संचालन को देखते हुए निर्वहन करने के लिए बाध्य था।

28. अलग-अलग शब्दों में कहें तो 1959 के नियमों के उक्त नियम 338 के संचालन के संबंध में, हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

" कंपनी की परिसंपत्तियों को संरक्षित करना, प्राप्त करना या प्राप्त करना और इस प्रकार, अपीलार्थी ओ. एल. द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करना होगा। 29. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हमें विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों पर विस्तार करना आवश्यक नहीं लगता है।

दलों को। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान मामले में बिक्री सूचना के नियमों और शर्तों में अस्पष्टता और चूक स्पष्ट रूप से इस स्थिति को जन्म देती है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

30. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ये अपील विफल हो जाती हैं और इसलिए खारिज कर दी जाती हैं। कोई लागत नहीं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे (सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

